इत्यादि के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकते हैं ।

देश में बेरोजगारी

697.**प्रो.रामबख्श सिंह वर्मा**:

श्रीमती मामती शर्मा:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर,1998 की स्थिति के अनुसार देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं,

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही हैं,

(ग) यदि हां,तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं,और

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत तक बेरोजगारी की समस्या का हल होने की संभावना हैं?

श्रम मंत्री (**डा.सत्यनारायण जटिया**): (क) और(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित नवीनतम श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 1987-88 के दौरान 12 मिलियन बेरोजगारी सामान्य मुख्य स्तर (यूपीएस) (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार 1993-94 के दौरान घट कर 9 मिलियन रह गई हैं ।

(ग) और (घ) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार व गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है । बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में सैक्टरों,सब-सैक्टरों तथा श्रम सघन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास प्रक्रिया में स्वत: ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा ।

अनुमार है कि यदि 2007तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है तो रोजगार वृद्वि की दर 2.8 प्रतिशत वार्षिक रखनी होगी ।

Guidelines for Wage Settlement

698. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANIAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the new guidelines issued to the Public Sector undertakings by the Department of Public Enterprises that wage settlement should now be for a period of ten years instead of the current practice of five years;

(b) if so, what are the details of the guidelines issued in this regard;

(c) whether the major central trade unions have opposed these guidelines; and

(d) if so, the details thereof and Government's response thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) Yes, sir. The Justice Mohan Committee has recommended that pay package and perquisites for officers and non-unionised supervisors, should be revised every 10 years instead of 5 years as has been the practice so far. The Government in their guidelines for the policy to be adopted for the Sixth round of wage negotiations in the Public sector enterprises have stated that in the event of the Government accepting the above recommendations, the revision of wages of the workers should be effected once in 10 years in order to ensure uniformity.

(c) No representation has been received so far from any major central trade union opposing recommendation of the Mohan Committee.

(d) Does not arise.

National wage Structure for Workers in Sugar Industry

699. SHRl JALALUDIN ANSARI:
SHRI J. CHITHARANIAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to set up a sub committee for deciding the national wage structure for workers in the sugar industry;

(b) if so, the criteria for selecting the members of the said committee, and

(c) the names of the members along with their affiliation, if the committee is already constituted?